भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2591
जिसका उत्तर मंगलवार 10 मई, 2016 को दिया जाना है

विद्युत वाहन

2591. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी उपयोग के लिए विद्युत वाहनों की खरीद हेतु एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव किफायती होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने प्रदूषण को रोकने के लिए विद्युत वाहनों का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे राज्यों को प्रदान किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ): जी, हां। कुछ राज्यों ने विद्युत वाहनों का उपयोग करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। विभाग ने (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राज्यों के लिए अधिकतम ₹1.5 करोड़ के लिए बस की 75% लागत का वित्तपोषण करने के माध्यम से 2 (दो) ई-बसों के वित्तपोषण का अनुमोदन दे दिया है। तथापि, कोई राशि जारी नहीं की गई है।

****